



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032023-244163
CG-DL-E-06032023-244163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1014]
No. 1014]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2023/फाल्गुन 15, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2023/PHALGUNA 15, 1944

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023

का.आ. 1055(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के तहत, स्वैच्छिक आधार पर, हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए, कैदियों को अन्य बातों के साथ, विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने हेतु, जैसे सुधारात्मक सुधार उपाय, स्वास्थ्य, कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मुलाकातियों के साथ मिलने, कानूनी सहायता, आदि जिनके वे हकदार हैं, उनके आधार अधिप्रमाणन निष्पादन के लिए, प्राधिकृत किये जाने पर, एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कारागार विभाग, कैदियों के आधार अधिप्रमाणन निष्पादन हेतु अधिकृत होंगे।

2. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कारागार प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधार अधिप्रमाणन के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

[फा. सं. 17013/31/2022-पीआर]

अरुण सोबती, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2023

S.O. 1055(E).—The Ministry of Home Affairs having been authorized by the Central Government to notify, under Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section 4 of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, performance of Aadhaar authentication of prison inmates on a voluntary basis using Yes/No authentication facility, inter-alia, for delivery of various benefits/facilities to which they are entitled, such as, correctional reform measures, health, skilling, vocational training, interview with relatives, legal aid, etc., hereby notifies that the Prisons Department of the States/Union Territories are allowed to perform Aadhaar authentication of prison inmates.

2. The Prison authorities of the States/ UTs shall adhere to the guidelines with respect to the use of Aadhaar authentication as laid down by the Central Government.

[F. No. 17013/31/2022-PR]

ARUN SOBTI, Dy. Secy.